सुभाषित *व्रताचरणसे ही मनुष्यको दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षासे दक्षिणा और दक्षिणासे जीवनके आदर्शोंमें श्रद्धा तत्पश्चात सत्यकी प्राप्ति होती है।* ❑ **यजुर्वेद**

संसदका शीतकालीन सत्र

संसदका शीतकालीन सत्र आज सोमवारसे प्रारम्भ हो रहा है, जो २० दिसम्बर तक चलेगा। सत्रके दौरान कई महत्वपूर्ण बिलोंपर चर्चा होगी। संसदका माहौल काफी गर्म रहनेके आसार हैं। सत्ता और विपक्ष दोनोंने अपनी-अपनी रणनीतियां बना ली है। विपक्ष सरकारको घेरनेके लिए जहां पूरी तरहसे तैयार है वहीं सत्तापक्ष अपने सहयोगी दलोंके साथ विपक्षपर आक्रामक रवैया अपना सकता है। महाराष्ट्र और झारखण्डमें हुए विधानसभा चुनावोंके बाद होने वाले शीतकालीन सत्रमें चुनावोंसे सम्बन्धित मुद्दे भी उठाये जा सकते हैं। रविवारको परम्पराके अनुसार हुई सर्वदलीय बैठकमें सदनके सुचारू संचालनकी बातें हुई लेकिन यह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है कि सदनका माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर रिपोर्टको मंत्रिमण्डलसे स्वीकृति मिलनेके बाद सम्बन्धित विधेयकको सत्रके दौरान पेश किया जा सकता है। इसपर विपक्षी दलोंका रवैया विरोधपूर्व रह सकता है। विपक्ष देशमें एक साथ चुनावके पक्षमें नहीं है। इसके अतिरिक्त वक्फ विधेयकपर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) शीतकालीन सत्रमें अपनी रिपोर्ट पेशकर सकती है। इसपर भी सदनमें हंगामेके आसार हैं। १८वीं लोकसभाका पहला मानसून सत्र २२ जुलाईसे ९ अगस्त तक चला था, तब २१ विधेयक पेश किये गये थे। इसमें चार विधेयक पारित हुए थे। केन्द्र सरकारने शीतकालीन सत्रके लिए वक्फ संशोधन सहित १६ विधेयक सूचीबद्ध किये हैं। इनमे पांच नये विधेयक शामिल हैं। इन पांचों प्रस्तावित कानूनोंमें एक सहकारी मुद्दा है। आठ विधेयक लोकसभामें लम्बित हैं और दो अन्य राज्यसभाके पास हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ा मुद्दा अमेरिकामें उद्योगपति गौतम अडाणीपर धोखाधड़ीके आरोपोंसे सम्बन्धित है। अमेरिकी अभियोजकोंने अडाणी और उनके भतीजे सागर अडाणीपर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियोंको रिश्वत देकर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल किया है। विपक्ष इस मामलेको संसदमें अवश्य उठायगा जिसपर काफी हंगामा हो सकता है। इसके साथ ही मणिपुरकी मौजूदा स्थिति और गंभीर प्रदूषणके मामले भी उठाये जा सकते हैं। सत्रके दौरान सदनका क्या स्वरूप रहेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। सदनके सुचारू संचालनमें सत्ता और विपक्ष दोनोंका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सत्रके दौरान एक दिन २६ नवम्बरको संविधान की ७५वीं वर्षगांठके अवसरपर संसद भवनके सेण्ट्रल हालमें संयुक्त सत्र आयोजित किया जायगा। शेष दिनोंमें संसदीय कार्यवाही होगी। सत्ता और विपक्ष दोनोंके तेवरपर ही निर्भर करता है कि कितने विधेयक पारित होते हैं।

आर्थिक संकटमें किसान

कृषि अब किसानोंके लिए लगातार घाटेका सौदा बनता जा रहा है। इसके मूलमें लागतके सापेक्ष आयमें भारी कमी है। अन्नदाता दो दशकसे अधिक समयसे अनवरत बढ़ते संकटका दंश झेल रहे हैं लेकिन अबतक कोई सार्थक हल नहीं निकाला जा सका जिसे सरकारकी विफलता ही कहा जायगा। अपनी समस्याओंको लेकर किसान आन्दोलित हैं जिससे स्थिति असहज हो गयी है। शम्भू बार्डरपर आन्दोलनरत किसानोंकी शिकायतोंका हल निकालनेके लिए उच्चतम न्यायालयने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयके पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंहकी अध्यक्षतामें बीते दो सितम्बरको उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी जिसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट कोर्टमें दाखिल कर दी है। रिपोर्टमें इस बातका खुलासा अत्यन्त चिन्ताका विषय है कि किसानोंकी लागत और कृषिके लिए लिये गये ऋणका बोझ बढ़ रहा है लेकिन कृषि उपज नहीं बढ़ रही है। रिपोर्टमें कृषि संकटके कारणोंके बारेमें विस्तार से जानकारी दी गयी है जिनमें स्थिर उपज, बढ़ती लागत और कर्जके साथ ही अपर्याप्त मार्केटिंग सिस्टम शामिल हैं। हरितक्रांतिके शुरुआती लाभके बाद उपज और उत्पादन वृद्धिमें ठहरावका जो संकट शुरू हुआ वह अब तक बना हुआ है। हालके दशकोंमें किसानों और कृषि श्रमिकोंपर कर्ज कई गुना बढ़ गया है। अपर्याप्त मार्केटिंग सिस्टम और सिकुड़ते कृषि रोजगारसे कृषि आय वृद्धिमें गिरावट आयी है। कृषि श्रमिकोंके साथ-साथ छोटे और सीमान्त किसान इस आर्थिक मंदीसे सबसे अधिक प्रभावित हैं। दैवी आपदा भी कृषि क्षेत्र और खाद्य सुरक्षाको बड़े पैमानेपर प्रभावित कर रहे हैं जिनसे निबटना बड़ी चुनौती है। किसानोंकी खुशहाली के लिए केन्द्र और राज्य सरकारोंको विशेष ध्यान केन्द्रित करनेकी जरूरत है। किसान समृद्ध होंगे तभी देश समृद्ध होगा।

लोक संवाद

नयी व्यवस्थासे टूटे किराना व्यवसायी

महोदय,-अमेरिकामें नये राष्ट्रपति चुने जानेके बाद इस मुद्देपर खूब सारी चर्चा हुई कि भारतके साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे। दिलचस्प है कि विशेषज्ञोंके बीच कूटनीतिक और रक्षा मसलोंपर थोड़ी मत भिन्नता जरूर दिखी परन्तु आर्थिक मुद्दोंपर ज्यादातरकी राय एक जैसी थी। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत दुनियाके लिए आज भी बड़ा बाजार है। उपभोक्ताओंके मामलेमें हम काफी आगे हैं और कई भावी संभावनाओंसे भी लैस हैं। यही नहीं, उपभोगकी भारतीय परम्परा और प्रवृत्ति भी बाजारको भाती है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के मुताबिक भारतका सतत उपभोक्ता सामान बाजार वित्त वर्ष २०२९-३० तक पांच लाख करोड़ रुपयेका हो जायगा और २०२७ तक हम दुनियाका चौथा सबसे बड़ा बाजार होंगे। इससे देशके भीतर एक नयी स्थिति भी पैदा हो रही है। क्विक कॉमर्सकी शक्लमें घरतक उपभोक्ता वस्तुओंकी खरीदने भारतकी पारम्परिक बाजार व्यवस्थाको पूरी तरह बदलकर रख दिया है। भारतकी घरेलू बाजार व्यवस्था किस तेजीके साथ बदल रही है, वह इस बातसे समझा जा सकता है कि बीते एक सालमें कमसे कम दो लाख किराना स्टोर या पड़ोसके छोटे रिटेल आउटलेट बंद हो चुके हैं। यह तथ्य इसी माह आल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (एआईसीपीडीएफ) के अध्ययनमें सामने आया है। इसके मुताबिक भारतीय उपभोक्ता तेजीसे ब्लिंकिट, ओटीपी और जेप्टो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफार्मोंकी ओर रुख कर रहे हैं। यह अध्ययन देशके करीब १.३ करोड़ ऐसे स्टोरके साथ किया गया है, जो किराना और पर्सनल केयरके सामान बेचते हैं। अध्ययन बताता है कि बंद होनेवाले स्टोर्समें ४५ प्रतिशत महानगरोंके हैं। टियर-१ शहरोंके ३० और टियर-२ एवं तीन शहरोंके २५ प्रतिशत स्टोर्स बंद हुए हैं। क्विक कॉमर्स फर्म ग्राहकको लुभानेके लिए प्रीडेटरी प्राइसिंग या भारी छूट दे रही हैं और लागतसे कम दामपर बेच रही हैं। इसने एक अनफेयर प्लेइंग फील्ड बना दिया है, जिससे ग्राहक बेस और किराना स्टोरोंकी मुनाफेकी क्षमता गिर रही है। भारतमें बाजार और समाजका एक साझा चरित्र भी है, जो हमारे रोजमर्राकी जिन्दगीमें साफ तौरपर उभरता है। कस्बे-मोहल्लेसे लेकर पास-पड़ोसमें खुले किराना दुकानोंकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सामाजिक विश्वसनीयता और आत्मीय व्यवहार रहा है। लेकिन यह सब मुनाफे और बचतकी नयी बाजार व्यवस्थामें औंधे मुंह गिर रही है। कायदेसे नयी बन रही स्थितिने हमारे घर-परिवार और समाजको नये तरहसे गढ़ना शुरू कर दिया है। इस स्थितिका ज्यादा गहराईसे अध्ययन किया जाना चाहिए कि बाजारके साथ जुड़े हमारे सामाजिक संबंध और सरोकार यदि कमजोर पड़ते हैं तो इसका असर हमारे विचार और स्वभावमें क्या पड़ेगा। ऐसी ही कुछ चिन्ताओंको ध्यानमें रखते हुए हिन्दुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया और नेस्ले इंडिया सहित प्रमुख कम्पनियोंके चार लाख खुदरा वितरकोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली देशकी सबसे बड़ी संस्था एआईसीपीडीएफने इस संबंधमें वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयसे मांग की है कि वह इस बदलावको गहनतासे देखे-समझे और नियंत्रित करे। वैसे तो भारतके रिटेल बाजारके स्वरूप और प्रसारमें परिवर्तन कोई नयी बात नहीं है। बीते दो-ढाई दशकोंमें इस बारेमें कई सारे तथ्य सामने आये हैं और नयी बन रही स्थितियोंके साथ भारतीय उपभोक्ता समाज लगातार अभ्यस्त भी होता जा रहा है। लेकिन बीते एक दशकमें जो रुझान सामने आये हैं, वे चौंकाते हैं। वैसे भी ये बदलाव ऐसे समयमें हुआ है जब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) पहलेसे ही कथित स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग और अन्य अनुचित प्रथाओंके लिए ऑनलाइन कॉमर्स प्लेयर्सकी जांच कर रहा है। सीसीआईने एक आंतरिक रिपोर्टमें पाया कि ई-कॉमर्सकी प्रमुख कम्पनियों अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्टने अपने प्लेटफॉर्मपर चुनींदा विक्रेताओंको वरीयता देकर तय दिशा-निर्देशोंका उल्लंघन किया है। साफ है कि हमारे पास-पड़ोसमें किराना दुकानोंके कुछ बचे-खुचे साइनबोर्ड हैं, वे भी अगले कुछ समयमें उतर जायंगे। ऐसेमें भारतीय उद्योग और व्यापार जगतकी यह चिन्ता मायने रखती है कि क्विक कॉमर्स फर्मोंकी आर्थिक रचनाकी जांच की जाय। कथित प्रीडेटरी प्राइसिंग जैसी रणनीतिसे आगे बढ़नेवाली इन फर्मोंके लिए दिशा-निर्देश तो बनने ही चाहिए, इस बारेमें कानूनी चुस्ती भी जरूरी है। इस लिहाजसे वित्तमंत्रीका यह आश्वासन महत्वपूर्ण है कि सरकार क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स प्लेयर्सकी स्ट्रेटेजिक प्राइसिंगसे नुकसान उठानेवाले कारोबारियोंके हितोंकी रक्षाके लिए गम्भीरतासे विचार करेगी। -**पी. प्रकाश, वाया ईमेल।**

भारतसे लाभान्वित समूह बीस

जी-२० का १९वां शिखर सम्मेलन ब्राजीलके रियो डी जेनेरोमें संपन्न हो गया। प्रतिवर्ष आयोजित होनेवाला यह सम्मेलन, गत दो दशकोंसे लेकर विद्यमान वैश्विक समस्याओंके समाधानके उद्देश्यसे आयोजित होता रहा है, किंतु निरंतर आगे बढ़ते एवं आधुनिक होते समयमें विश्वकी समस्याओंका स्वरूप भी परिवर्तित होता रहा है।

❑ **विकेश कुमार बडोला**

जी-२० सम्मेलनमें कुछ ऐतिहासिक घोषणाएं हुई हैं। प्राय: हर आयोजनकर्ता देश अपनी विद्यमान समस्याओंके आधारपर भी सामूहिक घोषणाओंमें कुछ बिन्दु उल्लिखित करता है। इसलिए ब्राजीलने भी देशकी गरीबी, भुखमरी, बीमारियों और शेष विश्व, विशेषकर विकसित देशोंके साथ आर्थिक-व्यावसायिक समन्वयनमें उत्पन्न होनेवाली बाधाओंके संबंधमें विचार रखे, जिन्हें अंतिम घोषणा-पत्रकी प्रमुख कार्यकारी सूचीमें सम्मिलित किया गया है। इस समय सम्पूर्ण जगत विनाशक, भयंकर और विभीषक समस्याओंसे ग्रस्त है। रूस तथा यूक्रेनके आमने-सामनेके सैन्ययुद्धकी अवधि एक हजार दिनोंसे अधिक हो चुकी है। इसरायल तथा फिलीस्तीन, ईरान एवं अन्य मुसलिम देशोंका सैन्ययुद्ध भी डेढ़ वर्षसे हो ही रहा है। युद्धोंमें प्रयोग होनेवाले आधुनिक अस्त्र-शस्त्रोंके कारण तात्कालिक रूपमें तो युद्धग्रस्त भू-भागों और अंतरालमें सम्पूर्ण पृथ्वीपर जलवायुकी अस्थिरताएं बढ़ रही हैं। प्रकृति असंतुलित तथा अनियमित हो रही है। युद्ध सामग्रियोंके निर्माणमें व्यस्त विश्वकी विशालतम अनेक आयुध निर्माणियोंके दिन-रात्रिके परिचालनके कारण भी अनेक रासायनिक तत्व वायुमंडलमें घुल रहे हैं। निर्माणियोंका अपशिष्ट भी भूमिके अन्दर प्रवेश कर वन-वनस्पतियों तथा खाद्यान्नको स्वास्थ्यके प्रतिकूल बना रहा है। इन परिस्थितियोंमें कुछ दिवस पूर्व अजरबैजानके बाकूमें सीओपी २९ की संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उपाय संबंधी शिखर-वार्ता भी संपन्न हुई है। जलवायु संबंधी निष्कर्षको देशों द्वारा समूह २० के घोषणा-पत्रमें भी प्रमुखतासे सम्मिलित किया गया है। इसी आधारपर जलवायु अनुकूलन नीतियोंके क्रियान्वयनको जी-२० के सदस्य राष्ट्रोंने अग्रणी वैश्विक कार्यक्रम बनाया है। साथ ही समूहकी वार्ता-सूचीमें सामाजिक समावेशन, भूख और गरीबी निवारण, अरबपतियोंके कराधान हेतु समर्थन, ऊर्जा संक्रमणके उपाय, वैश्विक शासनमें सुधार और २०२५ में ब्राजीलके बेलेम डू पारामें होनेवाले सीओपी ३० के लिए अनिवार्य समर्थन जैसे कार्य भी समाविष्ट किये गये हैं।

जी-२०के १९वें सम्मेलनको देखें तो गर्वकी अनुभूति होगी। सभी देशोंकी दृष्टिमें भारतका महत्व अप्रतिम रूपमें बढ़ा है। समूह बीससे पृथक चीन, इटली,फ्रांस इत्यादि देशोंके साथ संपन्न भारतकी द्विपक्षीय वार्ताएं सिद्ध करती हैं कि विश्वकी हर समस्याके निवारणके लिए भारतकी भूमिका आश्चर्यजनक रूपमें सर्वाधिक अपेक्षित हो चुकी है। इस समय संपूर्ण दुनियामें एकमात्र भारत ही ऐसा देश है, जो मानवता तथा वैश्विक कल्याणके सत्यनिष्ठ दृष्टिकोणके साथ विकसित देशोंकी अग्रणी पंक्तिमें खड़ा होनेके लिए सबसे अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है।

समूहने उपरोक्त विषयोंके दिशा-निर्देशनमें ही विभिनन वैश्विक चुनौतियोंका निस्तारण करने तथा इनके आधारपर सशक्त, स्थायी, पर्यावरण अनुकूल एवं समावेशी विकासको बढ़ानेके संकल्पपर हस्ताक्षर किये हैं। वर्तमानकी भू-पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, आधुनिक और औद्योगिक विकासकी तीन-चार सौ वर्षोंकी निरन्तरताके कारण अति प्रतिकूल हो चुकी है। यह आभास न चाहते हुए भी दुनियाके प्रत्येक वयस्क व्यक्तिको है। इसी अनुभवके साथ बीस देशोंके प्रमुख व्यक्तियोंने अस्थिर जलवायुको वार्ताका केन्द्रीय विषय बनाया है। संभवत: इसी दिशादृष्टिके साथ भारतके प्रधान मंत्री मोदी सहित लगभग सभी नेता जलवायु परिवर्तनके विषयको संबोधित करने, न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमणको बढ़ावा देने और पर्यावरणको संरक्षित करनेके लिए समन्वित कारवाइयोंके महत्वपर बल देते रहे।

यह हर्षका विषय है कि समूहकी वार्तामें पेरिस समझौता गम्भीरतापूर्वक लागू करने, कार्बन तटस्थता लक्ष्योंके प्रति प्रतिबद्धताएं दर्शाने, विशेषकर विकासशील देशोंके लिए सार्वजनिक एवं निजी हरित वित्त वृद्धिके महत्वपर ध्यान देने जैसे विषय भी समाहित थे। इस संबंधमें तर्क दिया गया था कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचनामें सुधार द्वारा जलवायु अनुकूलन काररवाईको समुचित समर्थन प्राप्त हो सकता है। समूहने नव परिमाणित सामूहिक जलवायु वित्त लक्ष्यके लिए भी समर्थन व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा संक्रमणके संबंधमें विकासशील देशोंमें ऊर्जा संक्रमण हेतु निवेशका आह्वान और जीवाश्म ईंधनके लिए मिलनेवाली सब्सिडीको धीरे-धीरे समाप्त करनेकी प्रतिबद्धता दोहरायी गयी। समूह बीसका चिन्तन तो प्राय: दुनियाकी सभी समस्याओंका मिल-जुलकर समाधान ढूंढ़नेपर होता ही होता है, किन्तु वास्तविक धरातलपर समाधानके कार्यक्रम या तो देशोंके आन्तरिक राजनीतिक भ्रष्टाचारकी भेंट चढ़ते हैं या फिर देशोंकी स्वार्थ सिद्धिके चक्रव्यूहमें फंस कर रह जाते हैं। वर्ष प्रतिवर्ष यही होता रहा है। वास्तवमें समूह बीसकी कार्यकारी सूचीमें जो भी अधिक गम्भीर, कम गम्भीर अथवा सामान्य विषय समाहित होते हैं, उनका अपेक्षित क्रियान्वयन एक दीर्घ शासकीय-प्रशासकीय कार्य अभ्यासके माध्यमसे ही हो सकता है। साथ ही इन विषयोंकी क्रियात्मक परिणति इसपर भी अधिसीमातक निर्भर होती है कि किस देशमें किस वृत्तिका शासन या शासक है। यदि सत्यनिष्ठा, राष्ट्रीयता, मानवीयता, प्रकृतिवत्ताके भावों और दूरद्रष्टा विचारोंसे आन्दोलित कोई शासक सद्गुणात्मक होकर शासन करता है तो निश्चित रूपमें उसके नेतृत्वमें अथवा उसकी भागीदारी द्वारा समूह बीस जैसे मंचकी कार्ययोजनाएं भी फलीभूत हो सकती हैं। किन्तु दु:ख है कि वर्तमानमें अधिसंख्य देशोंके प्रमुख ऐसी योग्यतासे वंचित हैं। वे तो येन-केन-प्रकारेण वैश्विक प्रगतिवादको अपने-अपने देशोंके हितमें फलित होता हुआ देखना चाहते हैं। फिर भले ही इसके लिए जलवायु, प्रकृति, पर्यावरण तथा भू-पारिस्थितिकी कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो जाय। यदि देशोंका संदर्भ न भी लिया जाय और केवल समग्र विश्वके लोगोंके लोक-दृष्टिकोणसे प्रकृतिके संरक्षण हेतु व्यक्तिगत उपायके रूपमें सादगीपरक जीवन जीनेकी विनती की जाय तो अधिसंख्य लोग बेचैन हो उठेंगे। वे अपने चहुंओर आधुनिकताके प्रतिदानमें एकत्रित वस्तुओं-सेवाओंके मोहसे बुरी तरह बंधे हुए हैं। जबतक लोगोंमें स्वाभाविक आत्मपरिवर्तन नहीं होता कि उन्हें सादगीपरक जीवन जीकर पर्यावरणीय संतुलन साधना है, तबतक समूह बीस जैसे मंचोंकी वैश्विक लोककल्याण कार्ययोजनाएं फलीभूत होनेके बदले दिन-प्रतिदिन उलझती ही जायंगी।

यदि भारतकी दृष्टिसे जी-२० के १९वें सम्मेलनको देखें तो गर्व करने योग्य अनुभव होंगे। सभी देशोंके नेताओंकी दृष्टिमें भारतका महत्व अप्रतिम रूपमें बढ़ा है। समूह बीससे पृथक चीन, इटली, फ्रांस, इत्यादि देशोंके साथ संपन्न हुईं भारतकी द्विपक्षीय वार्ताएं सिद्ध करती हैं कि विश्वकी हर समस्याके निवारण हेतु भारतकी भूमिका आश्चर्यजनक रूपमें चिरपरिचित तथा सर्वाधिक अपेक्षित हो चुकी है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस समय सम्पूर्ण दुनियामें एकमात्र भारत ही ऐसा देश है, जो मानवता तथा वैश्विक कल्याणके सत्यनिष्ठ दृष्टिकोणके साथ विकसित देशोंकी अग्रणी पंक्तिमें खड़ा होनेके लिए सबसे अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। केवल समूह बीस ही नहीं अपितु सभी अंतरराष्ट्रीय मंच भारतकी सार्वभौमिक हितसाधक कार्यप्रणालियोंसे किसी न किसी रूपमें अवश्य लाभान्वित हो रहे हैं।

विश्वमें साख बढ़ानेकी प्रतिबद्धता

दुनियामें भारतका सम्मान दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। प्रधान मंत्री मोदी विश्व नेता बनकर उभरे हैं। विदेशी धरतीसे मिलनेवाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानोंकी शृंखला प्रमाण है कि मोदीकी छवि वैश्विक स्तरपर सर्वमान्य नेताके तौरपर स्थापित हुई है।

❑ **ललित गर्ग**

प्रधान मंत्री मोदीको डोमिनिका और गुयानाके सर्वोच्च नागरिक सम्मान और नाइजीरियाका दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है। कोरोना कालमें मानवीय दृष्टिसे मददका हाथ बढ़ानेके लिए डोमिनिकाने प्रधान मंत्री मोदीको डोमिनिका अवॉर्ड आफ ऑनर और गुयानाने ऑर्डर आफ एक्सीलेंससे नवाजा। दस वर्षोंमें प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीको कई देशोंने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानसे सम्मानित किया है लेकिन उनकी डोमिनिका, गुयाना और नाइजीरिया यात्राके दौरान उन्हें जो सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, वह हर भारतीयको अभिभूत कर देनेवाले हैं। ये सम्मान दुनियाभरके देशोंके साथ भारतके बढ़ते संबंधोंको भी दर्शाता है। अबतक विदेशोंमें कुल १९ बार प्रधान मंत्री मोदीको सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें महाशक्ति कहे जानेवाले देश रूस और अमेरिकाके अलावा मालदीव, फिलीस्तीन, इजिप्ट, बहरीन और युएई जैसे मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा बार विदेशी संसदको संबोधित करनेका रिकॉर्ड भी मोदीके नाम ही है। मोदीने अपने हर कीर्तिमानसे भारतका मस्तक ऊंचा किया है। आस्ट्रेलिया और ब्रिटेनके पार्लियामेंटको भी प्रधान मंत्री मोदी संबोधित कर चुके हैं। मोदीने १४ बार विदेशी संसदमें वहांके सांसदोंको संबोधित किया। अमेरिकामें मोदीने दो बार संसदको संबोधित किया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिजी, मॉरिशस, युगांडा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मालदीवकी संसदको भी प्रधान मंत्री मोदीने संबोधित किया है। इससे पहले प्रधान मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंहने सात बार, इंदिरा गांधीने चार बार, जवाहरलाल नेहरूने तीन बार, जबकि मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा रावने एक-एक बार विदेशी संसदोंमें सम्बोधन दिया है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तो सारे शासकीय प्रोटोकालको तोड़कर उस देशके प्रधान मंत्री जेम्स मारापेने न केवल मोदीका स्वागत किया साथ ही एयरपोर्टपर सबके सामने मोदीके पांव भी छूए। यह अभूतपूर्व है कि विश्वके इतिहासमें आजतक कभी भी किसी राष्ट्राध्यक्षने किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्षके पांव सार्वजनिक रूपसे नहीं छूए हो। भारतकी जनताने महानायक मोदीको एक नये भारतके शिल्पकारके रूपमें देखा। बात चाहे अमेरिका यात्राकी हो, वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी गले तो मिले ही साथ ही बाइडेनका यह कहना अपने आपमें अद्भुत है कि आप तो अद्भुत लोकप्रिय हो। मुझे तो आपके आटोग्राफ लेने चाहिए। आस्ट्रेलियाके सिडनीमें जिस तरहसे पूरा स्टेडियम वहां बसे भारतीयोंने ठसाठस भर दिया और पूरा स्टेडियम मोदी-मोदीके नारोंसे गुंजायमान हो उठा। उसे देखकर आस्ट्रेलियाके प्रधान मंत्री एंथोनी अल्बानीस भी हैरान रह गये।

आज भारत देशकी वैश्विक साख और गरिमामें जो वृद्धि हुई है उसका पूरा श्रेय प्रधान मंत्री मोदीको जाता है। विश्व शांतिकी स्थापनामें भारतका योगदान हो या प्रौद्योगिकीके विशाल क्षितिजमें लम्बी उड़ान, यह सब प्रधान मंत्रीकी विशाल दृष्टिसे संभव हो रहा है। हम सब बदलावकी इस प्रक्रियाको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह सौभाग्यसे कम नहीं है। मोदीका सम्पूर्ण व्यक्तित्व एक पाठशाला बन गया है। उनके व्यक्तित्वके कई अनूठे आयाम हम देख चुके हैं, जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। उनकी सबसे बड़ी और असाधारण बात है उनके वक्तव्य और भाषण। जितनी स्पष्टता और प्रभावी तरीकेसे वे अपनी बात रखते हैं वह विलक्षण है। उनकी दूरदृष्टि या विजन बिल्कुल स्पष्ट होता है। उन्होंने लोगोंमें विश्वास जगाया है कि भारतमें आर्थिक विकास करने और दुनियामें अपना प्रभुत्व कायम करनेकी क्षमता है। कठोर परिश्रम एवं अनुशासित जीवनके प्रति उनके अनुरागने दुनियाको प्रभावित और प्रेरित किया है। राष्ट्रीय स्वयसेवक संघमें एक बाल स्वयं सेवक बननेसे लेकर प्रधान मंत्री बननेतक उनका जीवन अनुशासित रहा है। स्वास्थ्यके प्रति सजग रहते हुए, हर पल उत्साहसे बिताना और नियमित योग करना उनकी दिनचर्या है। कई अवसर ऐसे आये जब मोदीने यह सिखाया और प्रयोग करके दिखाया कि कैसे धैर्य और विनम्रता सबसे भरोसेमंद साथी है। इनके सहारे कठिन चुनौतियोंसे निबटा जा सकता है।

प्रधान मंत्री मोदीमें समयके साथ चलने और समयके पार देखनेकी अद्भुत क्षमता है। इसीलिए उन्होंने अपने नेतृत्वमें जितनी योजनाएं बनायी वे सब वर्तमानको मजबूत बनाते हुए भविष्यको सुरक्षित करनेवाली योजनाएं हैं। वर्ष २०४७ तक विकसित भारत समृद्ध भारतका मिशन पूरा करने और भारतको विश्वकी प्रथम पांच अर्थव्यवस्थाओंमें शामिल करनेके महान लक्ष्यको पूरा करते हुए भारत एक महाशक्तिके रूपमें उभरते हुए विश्व नेतृत्वकी क्षमताओंको उजागर कर रहा है। मोदीकी सभी योजनाओंका उद्देश्य देशको विकसित बनाना और आर्थिक अर्थव्यवस्थाको सुधारना है। नागरिकोंको अच्छी सुविधाएं, आत्मनिर्भर जीवनयापनके अच्छे विकल्प, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा रोजगार, बेहतर वातावरण आदि उपलब्ध कराना है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्किल इंडिया मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, अमृत योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधान मंत्री उज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, आत्मनिर्भर भारतने वर्तमान भारतकी तस्वीर बदल दी है। भारतीय लोकतंत्रमें एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ है और उसमें निरन्तर नये-नये आयाम जुड़ते जा रहे हैं जिसे समूची दुनिया आश्चर्यसे देख रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वासके मंत्र अब हर नागरिकका सूत्र वाक्य है। मोदीके नेतृत्वमें कई परिवर्तनकारी पहल की गयी हैं, जिनका भारतपर स्थायी प्रभाव पड़ा है। उनके स्वच्छ भारत अभियानने पूरे देशमें स्वच्छता और सफाईके बारेमें जागरूकता बढ़ायी है, जबकि मेक इन इंडिया पहलका लक्ष्य भारतको वैश्विक विनिर्माण केन्द्रमें बदलना है। इसके अतिरिक्त मोदीके डिजिटल इंडिया कार्यक्रमने देशके डिजिटल बुनियादी ढांचेमें काफी सुधार किया है, जिससे प्रौद्योगिकी सभीके लिए अधिक सुलभ हो गयी है। दस वर्षका कुशल देश संचालन, विकासकी नयी इबारत लिखना, विश्वमंचोंपर भारतकी साखको बढ़ाना आदि घटनाओंके साक्षी रहे लोगोंका अनुभव है कि इस अवधिमें जितना एवं जैसा भारत बना है, उसमें विश्वको नयी दिशा देनेकी क्षमता है। भारतकी जनता उन्हें एक नये भारतके अभ्युदयके आधारस्तंभके रूपमें देख रही है।

आत्मबोध

मानवीय मूल्य

❑ **श्रीश्री रविशंकर**

आज हम पूरी दुनियामें मानवीय मूल्योंका विनाशकारी पतन देख रहे हैं। आवश्यकता है कि इस ऊर्जाको रचनात्मक मार्गकी ओर मोड़ा जाय। हमें ऐसा वातावरण बनाना है जहां दोष लगाने और कमियां निकालनेकी अपेक्षा सहायता और सहयोगको बढ़ावा दिया जाय। जहां अधिकारी कानून और नियमोंके पालनकी रक्षाके लिए उत्तरदायी हैं, वहीं हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि वातावरणसे तनावको दूर करने और समाजमें मानवीय मूल्योंको बनाये रखनेके लिए काम करें अन्यथा जिन लोगोंतक यह संदेश नहीं पहुंचा है, वह आक्रोशवश हमें और हमारे प्रियजनोंको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम सब लोगोंको बेहतर भारतके निर्माणके लिए कार्य करनेके लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए, कमसे कम सप्ताहमें कुछ घंटे। यदि कुछ ही लोग इस विशाल एवं उदार दृष्टिकोणवाले हो जायं, जो दूसरोंके भावनात्मक हितका उत्तरदायित्व ले सकें तो समाजके शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होनेकी बड़ी संभावना है। हम सब अपने वातावरणको तनावमुक्त रखनेके लिए छोटे-छोटे प्रयास तो कर ही सकते हैं। हमें अपनी खुशियां दूसरोंके साथ बांटना सीखना होगा। यदि आप प्रसन्न हैं तो अपनी प्रसन्नता दूसरोंके साथ बांटिये, इसे केवल अपनेतक सीमित मत रखिये। इस भावनाके साथ किया गया कोई भी कार्य सेवा है और दूसरोंकी मानसिक स्थितिको ऊपर उठाना सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन हां, हमें इस बातके लिए सजग और संवेदनशील रहना होगा कि अधिक उत्साहमें हम दूसरोंकी भावनाओंको ठेस न पहुंचाये। जो कुछ भी हमको प्राप्त है, जब हम उसे दूसरोंके साथ बांटते हैं तो ईश्वर और अधिक प्रचुरतासे वह आनन्द हमारे ऊपर बरसाता है। आध्यात्मिक होनेका यह अर्थ नहीं है कि दुनियाकी ओरसे आंखें फेर ली जायं। इसके विपरीत जितना अधिक आप स्वयंके बारेमें जानते जाते हैं, उतना अधिक ही आप दूसरोंके विषयमें जानने लगते हैं और उन चीजोंको भी जानने लगते हैं, जो सामने नहीं होती। कहीं न कहीं अन्दरसे हम सब यह जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम यहां क्यों है और हमारे जीवनका उद्देश्य क्या है। आध्यात्मिकताका अर्थ है आत्मज्ञानकी इस जिज्ञासाको जीवन्त रखना और इस लक्ष्यको कभी न छोड़ना। ये प्रश्न एक दिशा सूचक यंत्रकी तरह हैं, जो कि आपके जीवनको दिशा प्रदान करते हैं। प्रत्येक अंत राहत और पूर्णताका भाव लाता है और किसी भी कार्यका आरम्भ अपने साथ नयी आशा एवं उत्साह लाता है।

पाकिस्तानकी धूर्ततामें न फंसे भारतीय क्रिकेट टीम

❑ **आर.के. सिन्हा**

भारतने साफ कर दिया है कि उसकी क्रिकेट टीम आगामी साल पाकिस्तानमें होनेवाली आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफीमें भाग नहीं लेगी। इस तरहसे उसने दुनियाको एक सख्त और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जारी रहेगा, तबतक भारत अपने पड़ोसी मुल्कके साथ अन्य क्षेत्रोंमें भी सामान्य व्यवहारका दृष्टिकोण नहीं रख सकता। भारतीय क्रिकेट टीमका पाकिस्तानमें क्रिकेट न खेलना एक जटिल मुद्दा है, जिसके राजनीतिक और सुरक्षात्मक दोनों पहलू हैं। आपको इस तरहके कई पिलपिले तर्क देनेवाले मिल जायंगे कि खेलको राजनीतिसे अलग रखना चाहिए। क्रिकेटके माध्यमसे दोनों पड़ोसियोंके बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं। खेल प्रशंसकोंको एकजुट करता है और सद्भावनाका सन्देश देता है तो क्या हम इस काल्पनिक सद्भावनाके लिए अपने लोकप्रिय खिलाड़ियोंकी जान खतरेमें डाल दें। पाकिस्तानमें आतंकवादकी घटनाएं थमनेका नाम ही नहीं ले रही हैं। हालके दौरमें वहांपर दर्जनों चीनी नागरिकों और सेनाके जवानोंका कत्ल हो चुका है।

पाकिस्तानमें कई आतंकी संघटन सरकारके खिलाफ बागी तेवर अपनाते हुए आतंकी घटनाओंको अंजाम देनेमें खुलेआम लगे हुए हैं। क्या इन परिस्थितियोंमें हमें अपनी टीमको सीमाके उस पार भेजना चाहिए। कहना न होगा कि इस तरहका कोई भी कदम बहुत महंगा पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तानके बीच लम्बे समयसे राजनीतिक तनाव चल रहा है, जिसके कारण दोनों देशोंके बीच संबंध सामान्य नहीं हो सके, न तो होनेकी कोई संभावना ही दिख रही है। इसलिए सुरक्षा चिन्ताएं एक महत्वपूर्ण कारण हैं, राष्ट्रहितमें लिये गये इस निर्णयका! पाकिस्तानमें सुरक्षाकी स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहती। इसलिए भारतीय खिलाड़ियोंकी सुरक्षाको लेकर चिन्ता करना लाजिमी है। यह याद रखना होगा कि कुछ साल पहले पाकिस्तानमें श्रीलंकाकी क्रिकेट टीमपर भीषण हमला लाहौर शहरमें हुआ था। श्रीलंकाकी क्रिकेट टीमपर यह हमला ३ मार्च २००९ को हुआ था, जब लाहौरमें गद्दाफी स्टेडियमके पास एक बड़े काफिलेका हिस्सा श्रीलंकाई क्रिकेटरोंको ले जा रही एक बसपर १२ बंदूकधारियोंने गोलीबारी की थी। क्रिकेटर पाकिस्तानी क्रिकेट टीमके खिलाफ दूसरे टेस्टके तीसरे दिन खेलनेके लिए जा रहे थे। उस घटनाको सारी दुनियाने अपने टीवी सेटों और मोबाइल सेटोंपर देखा था। भारत यूं ही पाकिस्तानपर आतंकवादको बढ़ावा देनेका आरोप नहीं लगाता। पाकिस्तानने भारतपर बार-बार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे आतंकवादी हमले किये है। पाकिस्तानने ही १९४८, १९६५, १९७१ और कारगिलके युद्ध शुरू किये। यह अलग बात है कि उसे हर बार कसकर मार पड़ी। परन्तु वह तो एक नंबरका धूर्त है। उसे मार खानेमें ही आनन्द आता है।

हालांकि यह भी सच है कि पाकिस्तानसे उत्पन्न आतंकवादने भारतपर गहरा प्रभाव डाला है। दशकोंसे विभिन्न आतंकवादी समूहोंने भारतमें कई आतंकवादी हमलोंको अंजाम दिया है, जिससे बड़ी संख्यामें निर्दोष लोगोंकी मौत हुई है और सैकड़ोंको चोटें लगी हैं और बुनियादी ढांचेको व्यापक नुकसान पहुंचा है। इन हमलोंके परिणामस्वरूप भारतको व्यापक आर्थिक नुकसान हुआ है। मुंबईपर हुए २००८ के आतंकवादी हमलोंमें हुए नुकसानका आंकलन करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें मानवीय और आर्थिक दोनों तरहके नुकसान शामिल हैं। मुंबई हमलोंमें १६४ से ज्यादा लोग मारे गये, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। सैकड़ों लोग घायल हुए, कईको गहरी चोटें आयीं। उस भयावह हमलोंके बाद मुंबई पहलेकी तरह कभी नहीं हुई। हमलोंका उन लोगोंपर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा जो जीवित बचे, उनके परिवारों और समूचे शहरपर। यदि आर्थिक नुकसानकी बात करें तो हमलोंसे संपत्तिको व्यापक नुकसान हुआ, जिसमें होटल, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। मरम्मत और पुनर्निर्माणकी लागतका सटीक आकलन तो नहीं किया जा सकता। पर्यटन उद्योगपर भारी प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापारमें गिरावट आयी और सैकड़ोंकी नौकरियां चली गयीं। यह आर्थिक नुकसान दीर्घकालिक था। सारी दुनिया जानती है कि हमला पाकिस्तानके आतंकी संघटनोंसे किया था। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी २०२५ का आयोजन पाकिस्तानमें होना है। भारतने लाहौरमें अपने सभी मैचोंको दुबई में स्थानांतरित करनेका अनुरोध किया है, क्योंकि भारतीय सरकार अपनी टीमको पाकिस्तानमें खेलना नहीं चाहती। भारत पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवादसे लड़ने और साथ ही सामान्य व्यवहारको अपनानेकी दोहरी नीति नहीं अपनाना चाहता। यह पाकिस्तानको जम्मू और कश्मीरमें आतंकवादके लिए अपने छद्म समर्थनको वैध बनानेकी अनुमति देगा। पाकिस्तान इसलिए भारतीय टीमकी भागेदारी चाहता है कि यदि उसने भाग नहीं लिया तो सारा आयोजन चौपट हो जायगा। प्रायोजक नहीं आयंगे। जरा सोचिये कि जब पाकिस्तान चीनी नागरिकोंकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाता तो भारतीय टीमकी क्या करेगा। चीनके सामने तो सारी पाकिस्तान सरकार कटोरा लेकर खड़ी रहती है। पाकिस्तानमें बीते अक्तूबर महीनेमें कराची हवाई अड्डेके पास आत्मघाती हमलेमें दो चीनी नागरिक मारे गये और कमसे कम दस लोग घायल हुए हैं। विस्फोट सिंध प्रांतमें बिजली परियोजनापर काम कर रहे चीनी इंजीनियरोंके काफिलेपर हुआ था। पृथकतावादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए), जिसने हालके वर्षोंमें पाकिस्तानमें विकास परियोजनाओंमें शामिल चीनी नागरिकोंपर बार-बार हमले किये हैं, ने कहा है कि उसने हमला किया है। इसने कहा कि उसने कराची हवाई अड्डेसे आ रहे चीनी इंजीनियरों और निवेशकोंके एक काफिलेको निशाना बनाया। यह हमला उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान शंघाई सहयोग संघटन (एससीओ) के नेताओंके शिखर सम्मेलनकी मेजबानी करनेकी तैयारी कर रहा था। यह भी याद रखा जाय कि चीनियोंपर हमला उस वक्त हुआ था जब वहां इंग्लैंडकी क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेल रही है। जाहिर है, आतंकी हमलेके कारण पाकिस्तानका यह दावा तार-तार हो गया है कि वहां हालात सामान्य हैं। फिलहाल भारतको अपने स्टैंडपर कायम रहना चाहिए। भारतको अपनी क्रिकेट टीम किसी भी सूरतमें पाकिस्तान नहीं भेजनी चाहिए।